फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 33 प्रभात जयपुर, गुरूवार 3 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

All That Is Freedom

Every breath you take and every move you make, Every bond you break, every step you take, I'll be watching you

A Desert Craft That Reflects Light and Beauty

Lippan art is more than decoration, it became a way of bringing light, energy, and joy into desert homes

मोदी के प्रति नरम, शाह के खिलाफ आक्रामक शैली अपनाना सोची समझी रणनीति है?

गृह मंत्रालय की सदा से सख्त निर्णय लेने की परम्परा रही है, सख्त निर्णय लेने की जिम्मेवारी प्रायः गृह राज्यमंत्री पर डाली जाती है, जिससे गृह मंत्री सीधी आलोचना से बच जाते हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। ये है हमारे सपनों का भारत!

आज सुबह वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाह आशीष जोशी को नेहरू पार्क से मॉर्निंग वॉक के दौरान उठा लिया गया।

यह दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी, लेकिन इसके पीछे गृह मंत्रालय का हाथ बताया जा रहा है।

पूरे दिन यह पता नहीं चला कि उन्हें कहां ले जाया गया है। उनके ठिकाने का पता नहीं चल पाया। परिवार को भी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन सोशल मीडिया पर दिनभर यह घटना काफी सुर्खियों में रही और भारी हंगामा होने के बाद, शाम को जोशी को रिहा कर दिया गया।

पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने आशीष जोशी की रिहाई की जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा की।

उन्हें क्यों उठाया गया, इसके तत्काल कारण स्पष्ट नहीं हैं।

- पर, अब गृह राज्यमंत्री का पद उतना प्रभावशाली नहीं रह गया है। लगभग सभी निर्णय गृह मंत्री के स्तर पर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें ही सीधा टारगैट भी किया जा रहा है।
- कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने का निर्णय तक गृह मंत्री के आदेश पर लिया जाता है।
- कांग्रेस ने कहा, जंतर-मंतर प्रदर्शन में पैलैट गन से घायल छात्र की एफआईआर दर्ज करने में संसद मार्ग थाने को सात घंटे लग गए, जबकि खड़गे की उत्तराखंड यात्रा के दौरान हल्द्वानी के सभा स्थल के शुद्धिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर ली गई।
- कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री के खिलाफ ट्वीट करने या पॉडकास्ट करने पर भी लोगों को पकड़ा जा रहा है।

उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें गृह मंत्री और गृह सचिव के बीच जंतर-मंतर आंदोलन से निपटने के तरीके और वहां जुटे छात्रों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने को लेकर मतभेदों का जिक्र था।

ट्वीट के अनुसार, अमित शाह सख्त कार्रवाई चाहते थे, जबकि गृह सचिव ने इस तरीके के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि पुलिस बल इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई के पक्ष में नहीं है।

लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने तीखे अंदाज में आदेश दिया कि कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उसे अंजाम दे दिया गया।

निहत्थे छात्रों के खिलाफ हिंसा को लेकर संसद ठप रही। अमित शाह सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने नहीं आए कि पैलेटगन फायरिंग और हिंसा व बर्बरता की अन्य कार्रवाइयों का आदेश किसने दिया था।

क्या यही ट्वीट आशीष जोशी को पुलिस द्वारा उठाए जाने की वजह था? या इसके पीछे कुछ और कारण भी थे?

सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी में ओवैसी के करीबी आसिम वकार कांग्रेस में शामिल

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिम वकार बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे उनके पूर्व पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

- वकार, जो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ने कहा, वास्तव में सिर्फ कांग्रेस व राहुल गांधी ही भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम तो कांग्रेस व सपा से लड़ रही है और भाजपा को ही मजबूत कर रही है।

दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय, 24 अकबर रोड, में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आसिम वकार ने कहा कि एआईएमआईएम भाजपा का विरोध करने की केवल "जुबानी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी में धन सम्पन्न लोगों को टिकट देने का सोच रही है कांग्रेस

गत चुनाव में पार्टी का अनुभव बेहद खराब रहा, जब पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को पैसे भी दिए, पर वे बाद में निष्क्रिय हो गए और पैसे बचा लिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। सन् 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ जारी खींचतान के बीच, कांग्रेस मुख्य रूप से ऐसे सक्षम उम्मीदवारों को टिकट देने की योजना बना रही है, जिनके पास मजबूत आर्थिक आधार हो, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी की स्थिति मजबूत रह सके।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी इन महत्वपूर्ण चुनावों को गंभीरता से लड़ना चाहती है और इसलिए मजबूत जनाधार तथा पर्याप्त संसाधन रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

हालांकि, पदाधिकारी ने कहा कि जहां साधारण पृष्ठभूमि का कोई मजबूत उम्मीदवार वास्तव में जीतने की स्थिति में होगा, वहां अपवाद की स्थिति आने दी जाएगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, उम्मीदवारों से पार्टी फंड में योगदान देने की भी उम्मीद की जा रही है।

- वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के कई प्रत्याशियों को 70 लाख रूपए दिए थे, पर बाद में पता चला कि अधिकांश ने प्रचार पर पैसा खर्च नहीं किया और फंड बचा लिया, तब पार्टी ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर दो पर ही जीत मिली थी।
- कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, पार्टी इन महत्वपूर्ण चुनावों के लिए बेहद गंभीर है। इसलिए सक्षम व सम्पन्न उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और अगर साधारण पृष्ठभूमि का कोई प्रत्याशी चुनाव जीतने की स्थिति में होगा तो पार्टी उसे फंड देगी।
- कांग्रेस ने कहा, साधन सम्पन्न प्रत्याशियों से उम्मीद है कि वे पार्टी फंड में भी योगदान करेंगे।

पदाधिकारी ने कहा, "हमने पहले देखा है कि किस तरह गैर-गंभीर लोग टिकट ले लेते हैं और पार्टी से पैसे भी लेते हैं, लेकिन बाद में उस पैसे को अपने पास बचाने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

यह रणनीति 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अनुभव से प्रेरित लगती है। उस समय पार्टी ने कथित तौर पर कई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 70 लाख रुपये तक दिए थे।

चुनाव के बाद शिकायतें सामने आईं कि चुनाव प्रचार के लिए फंड पाने वाले कई उम्मीदवारों ने अपने प्रचार पर पर्याप्त खर्च नहीं किया और इसके बजाय पैसा खुद बचा लिया। उस समय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल की बाढ़ से बिहार में महामारी फैलने का खतरा बढ़ा

नेपाल की बाढ़ का पानी गंडक और कोसी नदी के जरिए बिहार में पहुँच रहा है, जिसमें इंसानों व जानवरों के मृत शरीर और मरी हुई मछलियाँ बहकर आ रही हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। पिछले सप्ताह से सामने आ रही तस्वीरों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। नेपाल से तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी नीचे की ओर आ रहा है और अपने साथ कीचड़, मलबा, तबाह हुए घर, मरे हुए जानवर और इंसानी शवों के अवशेष बिहार की नदियों में ला रहा है।

26 अगस्त को ऊंचाई वाले इलाके में ग्लेशियर के टूटने के बाद नेपाल में अचानक आई भयानक बाढ़ अब भारत में स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गई है। नेपाल में बचाव और राहत कार्य जारी हैं और 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 4,500 लोग अभी भी लापता हैं।

- बिहार सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, वे बाढ़ के पानी से मछलियाँ ना पकड़ें, ना ही उन्हें खरीदें या बेचें।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि बाढ़ का पानी सिर्फ पानी नहीं, इसमें सीवेज, कचरा आदि दूषित पदार्थ होते हैं, जब यह पानी ज़मीन के अंदर से कुओं, हैडपंपों या तालाबों तक पहुँच जाता है, तो स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव लम्बे समय तक दिखाई देता है।

यह आपदा नेपाल की सीमा पर नहीं रुकी।

त्रिशूली नदी का बाढ़ का पानी गंडक और कोसी के रास्ते बिहार में आ रहा है। इसके साथ बड़ी मात्रा में कीचड़, मलबा, मरी हुई मछलियां, जानवर और इंसानी शवों के अवशेष भी बिहार पहुँच रहे हैं।

बिहार में अब लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक वे बाढ़ के पानी से मछली न पकड़ें और न ही ऐसी मछलियां खरीदें, बेचें या खाएं। यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र के एक परिवार में 200 साल बाद हुआ कन्या का जन्म

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। महाराष्ट्र के बीड में एक परिवार में चार पीढ़ियों के बाद बेटी का जन्म हुआ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, एक शोभायात्रा में नवजात बच्ची को उसकी माँ के साथ रथ में बिठाकर ढोल, झांझ के साथ नृत्य करते हुए घर लाया गया।

- महाराष्ट्र के बीड जिले के दहीफाले परिवार में नवजात कन्या को माँ के साथ रथ में बिठाकर ढोल झांझ की ताल पर नाचते-गाते घर लाया गया।

नवजात बच्ची का नाम गार्गी रखा गया है। दहिफाले परिवार ने बताया कि करीब 200 वर्षों से उनके परिवार में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अपने बयानों से भाजपा को खुश करना बंद करें'

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेसी नेताओं, खासतौर से थरूर को चेतावनी दी और कहा, ऐसा करके आप लोग भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ हथियार थमा रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेताओं को ऐसे सार्वजनिक बयान देने से सावधान किया है, जिनसे भाजपा को राजनीतिक फायदा मिल सकता है। उन्होंने यह बात शशि थरूर द्वारा राहुल गांधी के जेन जी तक पहुंच बनाने को लेकर की गई टिप्पणियों के जवाब में कही।

वे थरूर की उस कथित टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम युवाओं के बीच उतना असर नहीं डाल सका, जितना कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों ने डाला।

- केसी वेणुगोपाल ने कहा, अगर कोई राहुल गांधी की गलती निकालता है या उनके खिलाफ एक दो नकारात्मक बातें बोलता है तो सबसे ज्यादा खुशी भाजपा को होती है।
- केसी वेणुगोपाल ने थरूर को निशाना बनाया, जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को वह समर्थन नहीं मिला, जो सीजेपी को मिला है। वेणुगोपाल ने कहा, मैंने कुछ मीडिया चैनलों में थरूर का बयान सुना है। मुझे यकीन है, उन्होंने जानबूझ कर कुछ नहीं कहा होगा।

वेणुगोपाल ने पत्रकारों से कहा, "मैंने उनका बयान केवल कुछ मीडिया चैनलों में प्रकाशित खबरों के जरिए देखा है। मैं यह ठीक-ठीक नहीं सुन पाया हूं कि उन्होंने क्या कहा था।"

उन्होंने कहा कि थरूर को अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को सावधानी बरतने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "भले ही कांग्रेस के सदस्य हमेशा पार्टी की व्यवस्था या अनुशासन का पूरी तरह पालन न करें, लेकिन हमें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिनका मकसद केवल भाजपा को खुश करना हो।"

वेणुगोपाल ने कहा, "अगर कोई राहुल गांधी में गलती निकालेगा है या उनके बारे में दो नकारात्मक बातें कहेगा है तो भाजपा बहुत खुश होगी। इससे उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर ने यह टिप्पणी जानबूझकर की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को राहत नहीं दी

नई दिल्ली, 02 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण में क्रीमी लेयर के मामले में केन्द्र सरकार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर अपने पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों को 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

- केन्द्र सरकार ने 11 मार्च के फैसले को लागू करने के लिये दो साल का समय मांगा था।

केन्द्र सरकार ने क्रीमी लेयर मामले में उच्चतम न्यायालय से 11 मार्च के फैसले को पिछली तारीख से लागू न करने और इसे लागू करने के लिए दो साल का समय देने की मांग की है। केन्द्र सरकार का कहना है कि इस फैसले का असर सरकारी नौकरियों, सर्विस और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिटायर्ड एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा, राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ बने

सीईओ पद के लिए 5,585 आवेदन मिले थे, इनमें से मिश्रा सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार पाए गए

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जीतेंद्र मिश्रा को 5,000 से अधिक आवेदकों की लंबी सूची में से राम मंदिर ट्रस्ट का पहला चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर (सीईओ) चुना गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 2 सितंबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा की।

पूर्व अधिकारी ने भारतीय वायुसेना में कई महत्वपूर्ण कमान संभाली हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। अब उनके सामने मंदिर के प्रबंधन और वित्तीय जवाबदेही की व्यवस्था को मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मिश्रा देवरिया जिले के रहने वाले हैं और इंटीग्रेटेड डिफैंस स्टाफ (ऑपरेशन्स) के उप प्रमुख भी थे।

एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) मिश्रा दिसंबर 1986 में लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। मई 2026 में 38 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद वे सेवानिवृत्त हुए। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे; एयर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल, बेंगलुरु; एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, अमेरिका तथा रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, ब्रिटेन के पूर्व छात्र रहे हैं।

अयोध्या में दान चोरी के विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में किए गए संरचनात्मक बदलावों का हिस्सा मिश्रा की नियुक्ति भी है। ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें अयोध्या के मदन मोहन पांडेय, दिल्ली के महेश भगचंदा और शिकोहाबाद की निर्मला यादव शामिल हैं।

- ट्रस्ट की बैठक में मिश्रा को सीईओ बनाने का फैसला किया गया। साथ ही अब तक कोषाध्यक्ष रहे गोविंद गिरी को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है और दिल्ली के महेश भागचंदा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- एयर मार्शल, दिसंबर 1986 में फाइटर पायलट के रूप में वायु सेना में शामिल हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले मिश्रा इंटीग्रेटेड डिफैंस स्टाफ के उपप्रमुख भी रह चुके हैं।

सीईओ पद के लिए ट्रस्ट को कुल 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे।

सर्च पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली ने की। इसमें सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और पूर्व वैज्ञानिक सुरेश हवारे भी शामिल थे।

आवेदकों का मूल्यांकन 600 अंकों की प्रक्रिया के तहत किया गया। अंतिम 16 उम्मीदवारों के साक्षात्कार 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में लिए गए।

ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि "तीन अत्यंत योग्य एवं प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स" की सिफारिश की गई थी। उम्मीदवारों का मूल्यांकन संस्थागत नेतृत्व, प्रबंधन विशेषज्ञता, ईमानदारी और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व की संस्था का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण जैसे मानकों पर किया गया।

प्रोफेशनल्स की नियुक्ति उन उपायों में से एक है, जिनके जरिए मंदिर ट्रस्ट लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करना चाहता है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहले ही इस बात पर जोर दे चुके थे कि दुनिया की सबसे चर्चित मंदिर परियोजना के लिए पूर्णकालिक सीईओ का होना प्रोफेशनल प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

यह फैसला ट्रस्ट की बैठक में लिया गया, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी कमलनयन दास, अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन, ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। नए फैसले के तहत कोषाध्यक्ष गोविंदगिरी को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है तथा महेश भागचंदा नए कोषाध्यक्ष हैं।

ट्रस्ट के अनुसार, सीईओ की जिम्मेदारी संस्था के स्वरूप और आकार के अनुरूप प्रणालियां, प्रक्रियाएं और संचालन व्यवस्था विकसित करना तथा संस्था के उद्देश्यों, प्रकृति और आकार के अनुरूप संगठनात्मक ढांचे का निर्माण और उसे मजबूत करने की होगी।

पूर्व वायुसेना अधिकारी मिश्रा इन सभी मानकों पर खरे उतरे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट पीजी में दुबारा परीक्षा देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, 02 सितंबर। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर नीट पीजी के 2,445 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष याचिका को मेंशन करते हुए कहा गया कि इन अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला उच्चतम न्यायालय के पहले के आदेश का उल्लंघन है।

- अदालत ने नीट के अन्य मामलों की सुनवाई कर रही बेंच के सामने मेंशन करने की सलाह दी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े मामले पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है, इसलिए इस मामले को उसी बेंच